महासमर में आत्मनिर्भर

आत्मनिर्भर भारत अभियान
विशेषांक

वर्ष : 2, अंक : 16 | 08 जुलाई, 2020

PERFORM INDIA
National Movement for Developed India

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि साहसिक और निर्णायक फैसले लेने वाले और विपरीत परिस्थितियों में भी चट्टान की तरह मजबूती के साथ डटे रहने वाले नेता की है। उनका अटूट विश्वास है कि एक आत्मनिर्भर व्यक्ति और राष्ट्र के पास ही हर चुनौती से टकराने का साहस और सामर्थ्य होता है।

हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 में सत्ता संभालते ही देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, लेकिन कोरोना संकट, अर्थव्यवस्था की धीमी रफ्तार और चीन की धोखेबाजी से उत्पन्न हालात से इस प्रक्रिया को और तेज करने की जरूरत महसूस हुई।

गरीब परिवार में पैदा होने के कारण प्रधानमंत्री मोदी आम आदमी के जीवन और उसकी कठिनाइयों को शिद्दत से अनुभव करते हैं। इसलिए उन्होंने कोरोना महामारी में सबसे अधिक प्रभावित गरीब, मजदूर और किसान को केंद्र बिंदु में रखते हुए छोटे उद्योगों पर फोकस किया। ताकि हर गरीब और गांव अपने दम पर खड़ा हो और मजदूरों को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिले। इससे महानगरों की ओर मजबूरी में होने वाले पलायन को रोकने में मदद मिलेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक चुनौती को अवसर में बदलते हुए आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया। 20 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक पैकेज की घोषणा कर न सिर्फ़ तात्कालिक जरूरतें पूरी कीं, बल्कि दीर्घकालिक उद्देश्यों को भी ध्यान में रखा। इससे गरीबों के स्वाभिमान की रक्षा के साथ ही देश की विकास यात्रा को एक नई गति देकर आत्मनिर्भर न्यू इंडिया का निर्माण किया जा सकता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘वोकल फॉर लोकल’ और ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ का मंत्र दिया। उन्होंने स्वदेशी उत्पाद खरीदने के साथ ही उनका गर्व से प्रचार करने की भी अपील की। उन्होंने हर वो चीज, जिसे आयात करने के लिए देश मजबूर है, वो भारत में ही कैसे बने और भविष्य में भारत उसका निर्यातक कैसे बने, इस दिशा में तेजी से काम करने पर बल दिया।

आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी काफी प्रतिबद्ध दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने अलग-अलग मंत्री समूह (जीओएम) की बैठकें कीं और सुझाव भी मांगा। कई मंत्रालयों ने अपने सुझाव देने के बाद कार्य योजना बनाकर काम भी शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट किया है कि भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है, तो आत्मकेंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता, बल्कि दुनिया के साथ प्रतिस्पर्धा करते हुए उसकी मदद करना चाहता है।

'आत्मनिर्भर भारत' के लिए पहल

- पीएम मोदी ने देश की जीडीपी का 10 प्रतिशत यानि 20 लाख करोड़ रुपये के ऐतिहासिक आर्थिक पैकेज की घोषणा की।
- मोदी सरकार ने अध्यादेश लाकर 'एक देश, एक कृषि बाजार' बनाने का मार्ग प्रशस्त किया।
- किसानों को अपनी फसल कहीं पर, किसी को भी बेचने की आजादी मिली।
- आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन कर कृषि उपजों को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया गया।
- गांव में ही श्रमिकों के हुनर की पहचान के लिए मैपिंग की शुरुआत की गई।
- GeM पर नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय उत्पादक देश की जानकारी देना अनिवार्य किया गया।
- घरेलू कंपनियों को अवसर देने के लिए 200 करोड़ रुपये तक की खरीद के लिए वैश्विक टेंडर पर रोक लगायी गई।

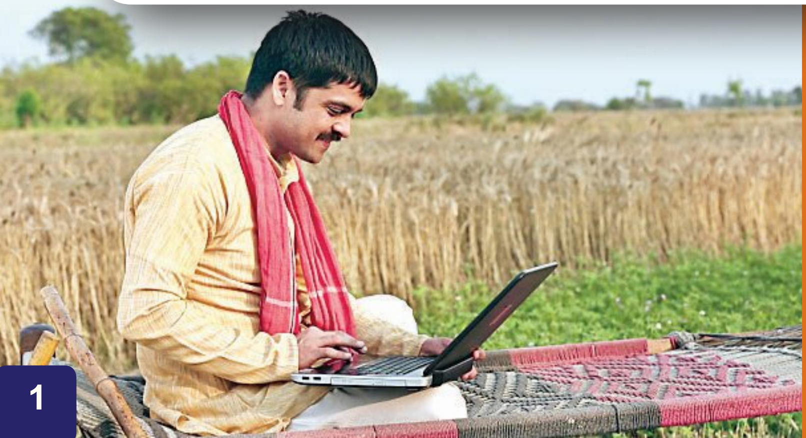

आत्मनिर्भरता लाएगी संपन्नता

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी

"आज हमारे पास साधन है, हमारे पास सामर्थ्य है, हमारे पास दुनिया का सबसे बेहतरीन टैलेंट है, हम बेस्ट प्रोडक्ट बनाएंगे, अपनी क्वालिटी और बेहतर करेंगे, सप्लाई चेन को और आधुनिक बनाएंगे, ये हम कर सकते हैं और हम जरूर करेंगे।"

"संकट के समय में, लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हमारी जिम्मेदारी है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा।"

"भारत की संस्कृति, भारत के संस्कार, उस आत्मनिर्भरता की बात करते हैं जिसकी आत्मा वसुधैव कुटुंबकम है। भारत जब आत्मनिर्भरता की बात करता है, तो आत्मकेंद्रित व्यवस्था की वकालत नहीं करता। भारत की आत्मनिर्भरता में संसार के सुख, सहयोग और शांति की चिंता होती है।"

आत्मनिर्भर भारत अभियान के पांच स्तंभ

अर्थव्यवस्था

एक ऐसी इकॉनॉमी, जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं, बल्कि क्वांटम जंप लाए।

बुनियादी ढांचा

एक ऐसा बुनियादी ढांचा, जो आधुनिक भारत की पहचान बने। विदेशी कंपनियों को आकर्षित कर सके।

सिस्टम

एक ऐसा सिस्टम,जिसमें आधुनिक तकनीक को अपनाने और समाज में डिजिटल तकनीक का उपयोग बढ़ाना शामिल है।

डेमोग्राफी

हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है, आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है।

मांग

हमारे पास बड़ा घरेलू बाज़ार और डिमांड क्षेत्र है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है।

आत्मनिर्भरता खत्म करेगी निर्धनता

- पीएम मोदी ने पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का नवंबर 2020 के अंत तक विस्तार करने की घोषणा की।
- 80 करोड़ से अधिक लोगों को नवंबर तक मुफ्त राशन प्रदान किया जाएगा।
- कोरोना संकट के समय 20 करोड़ गरीब परिवारों के जन-धन खातों में 31,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए गए।
- तीन महीने तक महिला जनधन खाताधारकों को प्रति माह 500 रुपये दिए गए।
- गरीब बुजुर्ग, माताओं-बहनों और दिव्यांगों के लिए 1000 रुपये की सहायता भी सीधे उनके खातों में भेजी गई।
- उज्ज्वला योजना के तहत गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस सिलिंडर दिए गए।
- 'एक देश एक राशन कार्ड' योजना के तहत एक ही राशन कार्ड से किसी भी शहर या राज्य में राशन मिल सकता है।

स्वावलंबी बनते किसान

- ◈ कृषि सेक्टर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये के एग्री-इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई।
- ◈ आवश्यक वस्तु अधिनियम में ऐतिहासिक संशोधन कर खाद्य वस्तुओं को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाया गया।
- ◈ किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सुविधा के हिसाब से कृषि उत्पाद खरीदने और बेचने का अधिकार दिया गया।
- ◈ किसानों की आधुनिक तकनीक और बेहतर इनपुट्स तक पहुंच भी सुनिश्चित की गई।
- ◈ बिचौलियों की भूमिका खत्म होने से किसानों को अपनी फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा।
- ◈ किसान सम्मान निधि के तहत अप्रैल-जून 2020 में 18,000 करोड़ रुपये 9 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में भेजे गए।
- ◈ स्थानीय उपज से अलग-अलग उत्पाद की पैकिंग वाली चीजें बनाने के लिए उद्योग समूह बनाए जाएंगे।
- ◈ लोकल उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए जिले में ही उद्योग लगाए जाने की योजना है।
- ◈ 1.5 करोड़ डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड्स (केसीसी) अभियान की शुरुआत की गई।
- ◈ महिला एसएचजी के लिए आजीविका के साधन के रूप में नर्सरी, हरा चारा, फलीदार प्रजातियों के रोपण को बढ़ावा दिया जा रहा है।
- ◈ हर्बल खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

कृषि से जुड़े हर क्षेत्र की मदद

- पशुपालकों और डेयरी सेक्टर के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का एक विशेष इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की घोषणा की गई है।
- मोदी सरकार ने मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ रुपये का आवंटन किया है।
- 20 हजार करोड़ रुपये की लागत से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई।
- नाबार्ड के जरिए अतिरिक्त आपातकालीन कार्यशील पूंजी सुविधा के रूप में 30,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
- कृषि क्षेत्र को 2 लाख करोड़ रुपये का ऋण प्रोत्साहन देने के लिए मिशन-मोड में अभियान चलाया जा रहा है।
- राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिस पर 13,343 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

आत्मनिर्भर बनते गांव

- गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उसकी जरूरतों के मुताबिक योजना बनाने और लागू करने पर जोर दिया गया है।
- टिकाऊ आधारभूत ढांचा और इंटरनेट जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
- गांव में ही रोजगार के अवसर सृजित करने वाले विकास कार्यों और क्षेत्रों की पहचान की जा रही है।
- महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ कर आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है।
- गांवों को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है।

आत्मनिर्भरता का आधार ग्रामीण उद्योग

अनाज प्रसंस्करण उद्योग, मृदा उद्योग, शक्कर और गुड़ प्रसंस्करण उद्योग, सुती कपड़ा बनाने का उद्योग, लकड़ी उद्योग, विविध कुटीर उद्योग

स्थानीय रोजगार

- कामगारों को घर के पास ही काम देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की गई है।
- इस अभियान को 6 राज्यों के 116 जिलों में लागू किया गया है, जिस पर 50,000 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- गांवों में रोजगार और विकास के कामों के लिए करीब 25 कार्यक्षेत्रों की पहचान की गई है।
- 2020-2021 के दौरान मनरेगा के तहत आवंटन बढ़कर एक लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया, जो एक रिकॉर्ड है।
- मनरेगा के तहत मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये की गई।
- जून 2020 तक 60.80 करोड़ श्रम दिवसों का सृजन किया गया और 6.69 करोड़ व्योक्तियों को कार्य प्रदान किया गया।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत 8 करोड़ मजदूरों और उनके परिवारों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया।
- 'वन नेशन वन कार्ड' के तहत प्रवासी मजदूर किसी भी शहर और राज्य में एफपीएस की दुकान से अपना राशन ले सकते हैं।
- प्रवासी श्रमिकों और शहरी गरीबों के लिए किफायती किराया आवास परिसरों के लिए योजना की घोषणा की गई।
- पीएम मोदी ने 26 जून, 2020 को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किया।
- लोकल प्रोडक्ट के लिए क्लस्टर बेस्ड अप्रोच को बढ़ावा देने से सभी के लिए अवसर उपलब्ध होंगे।

कामगारों का कौशल विकास

- कौशल विकास मंत्रालय कार्यबल की स्किलिंग, अप-स्किलिंग और री-स्किलिंग के लिए विशेष प्रयास कर रहा है।
- गांवों में श्रमिकों के हुनर मैपिंग की शुरुआत की गई है, ताकि श्रमिकों के कौशल के मुताबिक काम मिल सके।
- देश के 116 जिलों में तीन लाख मजदूरों को 10-15 दिन और तीन महीने के दो तरह के प्रशिक्षण देने का फैसला किया गया।
- मजदूरों को उनके पुराने कार्यक्षेत्र में ही हुनर को बेहतर बनाने के लिए 15 दिन के विशेष प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है।
- तीन महीने के प्रशिक्षण कार्यक्रम में मजदूरों को किसी नए क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण देकर कार्यकुशल बनाया जाएगा।
- प्रशिक्षण के दौरान संबंधित जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयों में प्रशिक्षित कामगारों की जरूरत को भी ध्यान में रखा गया है।
- 'स्वदेश' नामक एक आवेदन फॉर्म के माध्यम से स्वदेश लौटे लोगों को कौशल के आधार पर वर्गीकृत किया जा रहा है।
- इन लोगों को देश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है।

छोटे कारोबारियों का ख्याल

- रेहड़ी-पटरी वालों को अपनी आजीविका शुरू करने के लिए पीएम स्वनिधि योजना 01 जून, 2020 को लॉन्च की गई।
- स्ट्रीट वेंडर के लिए 5000 करोड़ रुपये की ऋण सुविधा दी गई, इससे 50 लाख स्ट्रीट वेंडर लाभान्वित होंगे।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग

◈ मोदी सरकार ने एमएसएमई को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए इसकी परिभाषा में संशोधन किया है।

◈ सूक्ष्म या माइक्रो इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 1 करोड़ रुपये और टर्नओवर 5 करोड़ रुपये होना चाहिए।

◈ छोटी इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 10 करोड़ रुपये और टर्नओवर 50 करोड़ रुपये होना चाहिए।

◈ मध्यम इकाई में निवेश की ऊपरी सीमा 50 करोड़ रुपये और 250 करोड़ रुपये का टर्नओवर होना चाहिए।

◈ संकटग्रस्त एमएसएमई के लिए 20,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, इससे 2 लाख एमएसएमई को मदद मिलेगी।

◈ फंड ऑफ फंड्स के माध्यम से एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ रुपये की पूंजी लगाए जाने को स्वीकृति दी गई है।

◈ एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ रुपये को आपातकालीन कार्यशील पूंजी की सुविधा दी गई है।

◈ सूक्ष्म खाद्य उद्यमों (एमएफई) को औपचारिक रूप देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की योजना शुरू की गई।

◈ एमएसएमई की सहायता और कारोबार के नए अवसर के लिए 'चैंपियंस' पोर्टल लॉन्च किया गया है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमई जीडीपी में 29 प्रतिशत और निर्यात में लगभग 50 प्रतिशत योगदान करते हैं। इस क्षेत्र में 11 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

वोकल फॉर लोकल

- 1 जुलाई, 2020 तक 13.69 करोड़ लोगों ने आरोग्य सेतु एप को डाउनलोड किया।
- देश के तकनीकी विशेषज्ञों ने इस विश्व स्तरीय एप को बनाकर अपनी क्षमता प्रदर्शित की।
- कोविड अस्पतालों को 50,000 'मेड इन इंडिया' वेंटिलेटर की आपूर्ति की गई।
- रक्षा मंत्रालय ने 26 सैन्य उपकरणों को केवल घरेलू आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदने का फैसला किया है।
- गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पर नए उत्पादों को पंजीकृत करते समय उत्पत्ति देश के बारे में जानकारी देना अनिवार्य।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र में बांस सेक्टर आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देगा।
- खादी और हैंडलूम की मांग और बिक्री कुछ ही समय में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई।

खादी और हैंडलूम की मांग रिकॉर्ड स्तर पर

6 साल में बिक्री में हुई जबरदस्त वृद्धि

वित्त वर्ष	करोड़ रुपये
2013-14	1081
2014-15	1310
2015-16	1664
2016-17	2146
2017-18	2510
2018-19	3215
2019-20	4211.26

क्षेत्रीय उद्योगों का पुनर्जन्म

- लोकल फॉर वोकल की वजह से कई पारंपरिक और स्थानीय छोटे उद्योगों को नवजीवन मिला है।
- वाराणसी में खादी और ग्रामोद्योग आयोग मिट्टी के बर्तन बनाने वाले समुदाय को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण दे रहा है।
- केवीआईसी ने कुम्हार सशक्तिकरण योजना के तहत वाराणसी में 1500 बिजली चालित पहियों (पॉटर व्हील) का वितरण किया।
- इलेक्ट्रिक पॉटर व्हील मिलने के बाद कई कुम्हारों की बिक्री में बढ़तोरी हुई है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

मेक इन इंडिया को बढ़ावा

- पीएम मोदी ने 4 जुलाई, 2020 को एप के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए एप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया।
- एप इनोवेशन चैलेंज का मंत्र है 'मेक इन इंडिया फॉर इंडिया एंड द वर्ल्ड'।
- भारत आज पीपीई किट का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है।
- सीएसआईआर-एनएएल ने 35 दिनों के भीतर बाईपैप वेंटिलेटर का विकास किया।
- वस्त्र समिति (मुंबई) ने पूर्ण रूप से स्वदेशी डिजाइन और 'मेक इन इंडिया' के तहत पीपीई जांच उपकरण बनाया।
- बिजली क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाइन टॉवर से लेकर, ट्रांसफार्मर और इन्सुलेटर तक देश में ही बनाने पर जोर दिया गया है।
- सभी सेवाओं में सरकारी खरीद व अन्य के लिए 'मेक इन इंडिया' नीति में संशोधन किया गया है।
- रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा दिया जाएगा।
- आयातित पुर्जों का स्वदेशीकरण किया जाएगा और इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान किया जाएगा।
- ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को कॉर्पोरेट का दर्जा दिया जाएगा और उनको शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध किया जाएगा।

“लोकल फॉर ग्लोबल”

- पीपीई किट के मामले में आत्मनिर्भर बनने के बाद 50 लाख यूनिट हर महीने निर्यात की मंजूरी दी गई है।
- देश में हर रोज 2 लाख एन-95 मास्क बनाए जा रहे हैं। इसके निर्यात की कोशिश भी की जा रही है।
- खादी लोकल से ग्लोबल बनने जा रहा है। खादी मास्क विदेशी बाजारों में दस्तक देने को तैयार है।
- केवीआईसी की योजना दुबई, अमेरिका, मॉरीशस,कई यूरोपीय और मध्य पूर्व के देशों में खादी फेस मास्क की आपूर्ति करने की है।

आत्मनिर्भरता की आत्मा वसुधैव कुटुंबकम

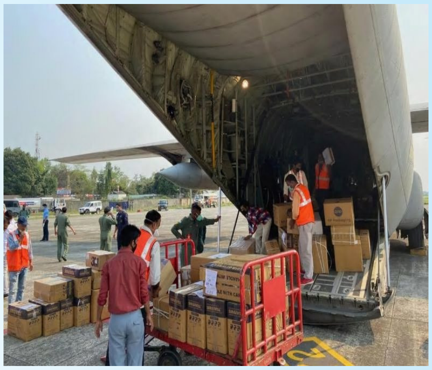

- जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाइयां आत्मनिर्भर भारत का संदेश लेकर पहुंचती हैं।
- आत्मनिर्भरता विश्व से अलग-थलग नहीं, बल्कि ग्लोबल सप्लाई चेन में कड़ी स्पर्धा के लिए देश को तैयार करेगी।
- विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सचिवों का एक एम्पावर्ड ग्रुप बनाया गया है।
- अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की पहल, मानव जीवन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उपहार है।
- इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ग्लोबल वॉर्मिंग के खिलाफ भारत की सौगात है।

देश की आवाज "आत्मनिर्भर भारत"

- ISRA के 211 मशहूर गायकों ने मिलकर 'जयतु जयतु भारतम' गाना तैयार किया।
- पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता की मिसाल पेश करने वाले गोंडा के स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से संवाद किया।
- ट्विटर पर #VocalForLocal टॉप ट्रेंड में रहा। इस मुहिम में अभिनेता अनुपम खेर और सांसद गौतम गंभीर शामिल हुए।
- चीनी सामानों के बॉयकॉट के लिए CAIT ने कैंपेन शुरू किया, बॉयकॉट के लिए 3 हजार उत्पादों की लिस्ट बनाई गई।
- वाराणसी में साड़ी व्यापारियों और बुनकरों ने चाइनीज़ रेशम से बनी साड़ियों के बहिष्कार का ऐलान किया।